खेती को उद्योग का दर्जा देने की जरूरत नहीं : सरयू राय

बीमा पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय

भास्कर न्यूज़ | कांके

खेती को खेती ही रहने दें। इसको उद्योग का दर्जा देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ घोषणा करने से यह उद्योग नहीं हो जाएगा। ये बातें मंत्री सरयू राय ने कही। वे बुधवार को बीएयू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि के रुप में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि इसी सोच ने फसल बीमा योजना को असफल बनाया। उन्होंने कहा कि किसान ही प्राथमिक उत्पादक है। उनके नुकसान की भरपाई के लिए बीमा की व्यवस्था की गई है। उन्होंने सभी किसानों से इसका पूरा लाभ उठाने को कहा। किसान को बीमा योजना देकर या राहत देकर सरकार कोई कृपा नहीं कर रही है। यह किसानों का हक है। किसानों को भी इसी प्रकार की सोच और समझ रखनी चाहिए तभी वे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने किसानों से वैज्ञानिकों की नई चीजों को अपनाने की बात कही। इस मौके पर बीएयू वीसी डॉ. जार्ज जॉन, जटाशंकर चौधरी, पवन बजाज, योगेश लोहिया, एसके सेठी सहित बड़ी संख्या चैंबर ऑफ कामर्स के पदाधिकार, किसान एवं पदाधिकारी मौजूद थे।

नि:शुल्क चिकित्सा शिविर 16 को

रांची : आर्किड मेडिकल सेंटर में 16 जुलाई को नि:शुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। शिविर में मरीजों की स्वास्थ्य जांच सर्जन डॉ. एसएस नारनौलिया करेंगे।

में स्कूल खुल ता कालजा म ग्राष्मावकाश शुरू हो गया जो 23 जून तक रहा। ऐसे में उनके सामने जुलाई में परीक्षा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

कक्षा नहीं होती, लेकिन पढ़ाई महंगी : राज्य में करीब 65 अंगीभूत व 66 संबद्धता प्राप्त कॉलेज

है। इनमें रांची कॉलेज को छोड़ सभी में इंटर की पढ़ाई होती है। अब इतने कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होने पर सवाल उठता है कि छात्र कहां जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा प्रस्वीकृति प्राप्त 105 इंटर कॉलेजों को होगा। लेकिन

स्कूल का संचाल
करता है और यह
तालिका को फॉलो
में समानता नहीं ह
पड़ता है। जैक के
कराना बड़ा मुश्कि

फसल बीमा किसानों के हित में

जागरण संवाददाता, रांची : केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा, बढ़ती जनसंख्या और खेती के लिए जमीन का घटता रकबा चिंता का विषय है। ऐसे में फसल बीमा योजना लाभ पहुंचा सकता है। किसानों की आजीविका पर सकारात्मक असर पड़ेगा, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। उद्योग और देश की समूची अर्थव्यवस्था की असल जड़ कृषि ही है। मानसून और दूसरे कारणों से कृषि को नुकसान पहुंचता है। इससे उद्योग जगत को भी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था बनाए जाने की जरूरत है जिससे किसानों को अपने कृषि उत्पाद, बाजार और बिचौलिए की चिंता ना हो। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बुधवार को पीएचडी चेंबर की ओर से फसल बीमा योजना पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय मुख्य अतिथि के तौर पर

कार्यक्रम का उद्घाटन करते मुख्य अतिथि।

मौजूद थे। उन्होंने कृषि योजनाओं में पारदर्शिता लाकर कृषक वर्ग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जॉर्ज जॉन ने कहा, 70 प्रतिशत आबादी अब भी कृषि पर ही आश्रित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदर्श योजना है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत संस्था और सिविल सोसाइटी के माध्यम से योजना को गांव-गांव तक ले जाने की जरूरत है।

एआइफुक्टो का मांग दिवस आज

रांची : ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन(एआइफुक्टो) की कार्यकारिणी में लिए गए फैसले के अनुसार 14 जुलाई को मांग दिवस मनाएंगे। साथ ही यूजीसी के चेयरमैन वेद प्रकाश को ज्ञापन भी सौंपेंगे। मंगलवार को फुटाज महासचिव डॉ. मिथिलेश और रुक्टा महासचिव डॉ. राजकुमार ने बताया कि देश के शिक्षक मांग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद पांच अगस्त को संसद मार्च होगा।

ये हैं मांगें : शिक्षकों के मुख्य मांग में 5वें व छठे वेतनमान एरियर का भुगतान, लंबित प्रमोशन का शीघ्र निष्पादन, अर्जित अवकाश 300 दिन करने, एपीआइ सिस्टम समाप्त करने, यूजीसी के 2010 के रेगुलेशन को शीघ्र वापस लेने, सीबीसीएस को वापस लेने सहित अन्य मांगे शामिल है।

बी

सीआइटी

जागरण संवाददा
मुख्यालय में बुधवा
छात्र-छात्राओं ने
प्रशासनिक भवन के
सभी वीसी कांफ्रेंस ह
को लेकर विवि अ
हुई। कुलपति डॉ. र
मामला परीक्षा बो
होगा। इसके बाद
मौके पर डीएसडब्ल्
नियंत्रक डॉ.आशीष
दिवाकर मिंज थे।
सत्यम चौबे, शुभम
ओमप्रकाश कर रहे

क्या है मामला : र
सेमेस्टर सत्र 2015-

RAJENDRA MEMORIAL RESEARCH

चिकित्सा शिविर 17 को

रांची : झारखंड मिथिला मंच व

बीएयू में प्रधानमंत्री फसल बीमा पर कार्यशाला

बेमेल होगा खेती को उद्योग का दर्जा देना : सरयू

वरीय संवाददाता

रांची। खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या और खेती के लिए जमीन का घटता रकबा चिंता पैदा कर रहा है। ऐसे में किसानों को बहुफसलीय तकनीक को अपनाना होगा। इससे न सिर्फ आजीविका पर साकारात्मक असर पड़ेगा,बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी दुरगामी प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने किसानों से किसान फसल बीमा योजना का लाभ लेने को कहा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में पीएचजी चैंबर,झारखंड द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आयोजित कार्यशाला में खाद्य आपूर्ति मंत्री ने ये बातें कहीं। सरयू ने कृषि को उद्योग का दर्जा दिए जाने की बात को बेमेल बताया। किसान को असली उत्पादनकर्ता बताते हुए कहा कि उद्योग और देश की समूची अर्थव्यवस्था की असल जड़ कृषि ही है। खेती को खेती का ही दर्जा बनाये रखें जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर मानूसन और दूसर कारणों से कृषि को नुकसान पहुंचता है तो समूचे उद्योग जगत को इसका नुकसान उठाना पड़ता हे। ऐसी व्यवस्था बनाये जाने की जरूरत है जिससे किसानों को अपने कृषि उत्पाद,बाजार और बिचौलिये की चिंता न हो। उन्होंने कहा कि कृषि योजनाओं में पारदर्शित लाने और धरातल पर अमल होने से कृषक वर्ग को स्वाभिमानी बन ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान,जय किसान का नारा दिया था, लेकिन अब जय किसान, जय बिज्ञान भी प्रासंगिक होगा। कार्यशाला का विषय प्रवेश पीएचडी चैंबर, झारखंड चैप्टर के चेयरमैन पवन बजाज ने कराया। मंच संचालन इंश्योरेंस कमिटी के प्रमुख योगेश लोहिया ने किया। धन्यवाद ज्ञापन देवजीत तालापात्रा ने किया। कार्यषाला में पीएचडी चैंबर के एसके सेठी,, दुर्गेष शर्मा, जितेंद्र नारायण सिंह, फरहा तबस्सूम, नीता प्रसाद, तथा विभिन्न बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के अलावा महिला कृषकों के अलावा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

उद्घाटन करते अतिथि।

योजनाओं को गांव तक ले जाने की जरूरतः कुलपति : बिरसा कृषि विष्वविद्यालय के कुलपति जॉर्ज जॉन के अनुसार देष की 70 फीसदी आबादी अब भी कृषि पर ही आश्रित है। देश की आजादी के बाद से ही किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं बनाए जाने पर सरकारों ने कदम उठाया है। पर वर्तमान की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदर्श योजना है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं, सिविल सोसाइटी के माध्यम से योजना को गांव-गांव तक ले जाने की आवश्यकता है।

बीमा योजना किसानों की आजीविका का रक्षा करेगीः कृषि निदेशक : कृषि निदेषक जटाशंकर चौधरी ने बताया कि झारखंड में औसतन 1300 मिली.तक बारिष होती है। सूखाड़ वाले समय में .ी 900 मिली. तक बारिष होती है। परंतु इसके बावजूद हमारे यहां कृषक समाज चुनौतियों से जुझ रहा है। परंपरागत कृषि पद्धति से बंधे होने के कारण नयी तकनीक अपनाने में सुस्ती और साल में एक बार महज धान उपजाने तक सीमित रहने के कारण उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। 38 लाख योग्य कृषि भूमि हमारे राज्य में है। परंतु 26 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही खेती हो पा रही है। फसल बीमा योजना इस समस्या के निदान की दिषा में एक पहल है। श्री चौधरी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के तहत सभी प्रकार की फसलों को शामिल किया गया है। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई .ी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकते हैं। राज्य में 14,000 कृषक मित्र हैं। किसान योजना का लाभ लेने को उनसे संपर्क कर सकते हैं। वर्तमान की बीमा योजना किसान और उनकी आजीविका के हितों की रक्षा करने में बेहद प्रभावशाली है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वरीय अधिकारी आरपी सिंह रतन ने भी संबोधित किया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर सेमिनार आयोजित

रांची : बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बुधवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में केन्द्र की इस योजना के बारे में वक्ताओं ने विस्तृत जानकारी दी और इसके फायदे बताये। सेमिनार में राज्य के खाद्य व संसदीय मामले मे मंत्री सरयू राय सहित पवन बजाज, योगेश लोहिया, कुलपति डॉ जार्ज जॉन, जटाशंकर चौधरी इत्यादि मौजूद थे और अपने विचार व्यक्त किये।

अधिकतर विद्यार्थी परीक्षा में फेल

ति का घेराव, पुनर्परीक्षा की मांग

'फसल बीमा योजना' पर आयोजित कार्यशाला में बोले मंत्री

बढ़ती जनसंख्या, घटती खेती चिंता का विषय

संवाददाता

रांची : खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सरयू राय ने कहा कि अधिक से अधिक किसान फसल बीमा योजना का लाभ लेने को आगे आयें। आज बढ़ती जनसंख्या और खेती के लिए जमीन का घटता रकबा चिंता पैदा कर रहा है। किसान बहुफसलीय तकनीक अपनाएं। इससे न सिर्फ उनकी आजीविका पर सकारात्मक असर पड़ेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। फसल के नुकसान की भरपाई की दिशा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री राय पीएचडी चैंबर, झारखंड चैप्टर के द्वारा बुधवार को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कृषि को उद्योग का दर्जा दिये जाने को बेमेल बताया।

खेती को खेती ही रहने दें, उद्योग का दर्जा न दें: श्री राय ने कहा कि कृषि को उद्योग का दर्जा न देकर इसे खेती ही रहने दें। किसान को असली उत्पादनकर्ता बताते हुए कहा कि उद्योग और देश की समूची अर्थव्यवस्था की असल जड़ कृषि ही है। अगर मानसून और दूसरे कारणों से कृषि को नुकसान पहुंचता है तो समूचे उद्योग जगत को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था बनाए जाने की जरूरत है जिससे किसानों को अपने कृषि उत्पाद, बाजार और बिचौलिये की चिंता ना हो। कृषि योजनाओं में पारदर्शिता लाने और धरातल पर अमल होने से कृषक वर्ग को स्वाभिमानी बनाया जा सकता है। श्री राय ने ने ह्यजय किसान, जय विज्ञानह्न को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। इससे पूर्व कार्यशाला की शुरुआत मंत्री, झारखंड चैप्टर के चेयरमैन पवन बजाज, इंश्योरेंस कमिटी के प्रमुख योगेश लोहिय, देवजीत तालापात्रा आदि अतिथियों ने दीप प्रज्जवलित कर किया। कार्यशाला में पीएचडी चैंबर के एसके सेठी, दुर्गेश शर्मा, जितेंद्र नारायण सिंह, फरहा तबस्सुम, नीता प्रसाद तथा विभिन्न बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के अलावा महिला कृषकों के अलाव सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

फसल बीमा योजना के प्रसार की जरूरत : जार्ज जॉन

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जॉर्ज जॉन ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि देश की 70 फीसदी अब भी कृषि करती है। किसानों के लिए देश की आजादी के बाद कई सरकारों ने योजनायें बनायीं पर वर्तमान में बनाया गया ह्यप्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाह्न एक आदर्श योजना है। इस योजना को संस्थाओं, सिविल सोसाइटी के माध्यम से गांव-गांव में प्रसार करने की जरुरत है।

कृषि के परंपरागत तरीकों से बंधे रहने के कारण किसान कठिनाई में : जटाशंकर

कृषि निदेशक जटाशंकर चौधरी ने बताया कि राज्य में कृषि योग्य उपलब्ध 38 लाख हेक्टेयर भूमि में मात्र 26 लाख हेक्टेयर पर ही खेती होती है। बारिश के मौसम में राज्यभर में औसतन 13 सौ मिली तक बारिश होती है। सुखाड़ वाले मौसम में भी 900 मिली तक बारिश होती है। इतने के बावजूद यहां के किसान कठिनाई में हैं क्योंकि कि यहां के किसान परंपरागत तरीकों को छोड़ कर अभी तक कृषि के नई तरीकों को अपनाने में पीछे हैं। फसल बीमा योजना किसानों के समस्याओं को दूर करने के लिए ही बनायी गई है। इसमें सभी प्रकार के फसलों को शामिल किया गया है। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसाना अपने नुकसान का अनुमान लगा सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर बीएयू में हुई संगोष्ठी, मंत्री सरयू राय ने कहा- राहत देकर सरकार कोई कृपा नहीं करती

फसल बीमा से किसानों के नुकसान की भरपाई

कांके | प्रतिनिधि

किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा की व्यवस्था की गई है। इसका सभी किसानों को लाभ उठाना चाहिए। यह बातें खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहीं। वह बुधवार को बिरसा कृषि विवि के कृषि संकाय सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आयोजित संगोष्ठी में बोल रहे थे। इसका आयोजन पीएचडी चैंबर की झारखंड शाखा ने किया था।

मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था विकसित देशों में भी हैं। हालांकि कहीं भी किसानों को ज्यादा लाभ दिला सकने की मुक्कमल योजना नहीं बन सकी है। किसान वैज्ञानिक खेती सीखें। कुछ लोग कृषि को उद्योग का दर्जा देने की हिमायत करते हैं। लेकिन घोषणा मात्र से यह उद्योग नहीं हो जाएगा। खेती को खेती ही रहने दीजिए।

उन्होंने कहा कि फसल बीमा की असफलता का कारण यह है कि इसको भी उद्योग क्षेत्र के इंश्योरेंस की तर्ज पर लिया गया। किसान ही सही उत्पादक है। किसान को बीमा योजना देकर या राहत देकर सरकार कोई कृपा नहीं कर रही है।

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बुधवार को आयोजित संगोष्ठी में अपने विचार रखते मंत्री सरयू राय व उपस्थित पदाधिकारी। • हिन्दुस्तान

चुनौतियों से जूझ रहे किसान

कृषि निदेशक जटाशंकर चौधरी ने कहा कि झारखंड में औसतन 1300 मिलीमीटर तक बारिश होती है। सुखाड़ वाले समय में भी 900 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। इसके बावजूद किसान चुनौतियों से जूझ रहे हैं। नई तकनीक अपनाने में सुस्त हैं। महज धान की खेती करने तक ही सीमित हैं। फसल बीमा योजना इस समस्या के निदान की दिशा में एक पहल है। इस योजना के तहत सभी प्रकार की फसलों को शामिल किया गया है। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकते हैं। राज्य में 14,000 कृषक मित्र हैं। किसान योजना का लाभ लेने को उनसे संपर्क कर सकते हैं।

बीएयू के निदेशक प्रसार शिक्षा डॉ आरपी सिंह रतन ने भी विचार रखे। विषय प्रवेश पीएचडी चैंबर के झारखंड चेयरमैन पवन बजाज ने कराया।

कार्यक्रम में मंच संचालन योगेश लोहिया और धन्यवाद ज्ञापन देवजीत तालापात्रा ने किया। मौके पर एसके सेठी, दुर्गेश शर्मा, जीतेंद्र नारायण सिंह, फरहा तबस्सुम, नीता प्रसाद सहित अन्य मौजूद थे।

गांवों तक ले जाएं योजना

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ जॉर्ज जॉन ने कहा कि देश की 70 फीसदी आबादी अब भी कृषि पर आश्रित है। आजादी के बाद से ही किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। वर्तमान की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदर्श योजना है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं, सिविल सोसाइटी के माध्यम से योजना को गांव-गांव तक ले जाने की जरूरत है।

कार्यक्रम . बीएयू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर कार्यशाला

बहुफसलीय तकनीक से खेती करें किसान : सरयू

पीएचडी चेंबर झारखंड चैप्टर द्वारा बीएयू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. मौके पर मंत्री सरयू राय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को महत्वपूर्ण कदम बताया.

संवाददाता ▸ रांची

पीएचडी चेंबर झारखंड चैप्टर ने किया था कार्यशाला का आयोजन.

पीएचडी चेंबर, झारखंड चैप्टर ने बुधवार को बिरसा कृषि विवि सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर कार्यशाला का आयोजन किया. खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए अधिक-से-अधिक किसान आगे आयें. उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या और खेती के लिए जमीन का घटता रकबा चिंता पैदा कर रहा है. इसके लिए किसान बहुफसलीय तकनीक अपनायें, इससे न सिर्फ उनकी आजीविका पर सकारात्मक असर पड़ेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे. फसल के नुकसान की भरपाई की दिशा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना महत्वपूर्ण कदम है.

श्री राय ने कहा कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना पूरी तरह से बेमेल है. उद्योग और देश की समूची अर्थव्यवस्था की असल जड़ कृषि ही है. खेती को खेती का ही दर्जा बनाये रखा जाये. अगर मानसून और दूसरे कारणों से कृषि को नुकसान पहुंचता है, तो समूचे उद्योग जगत को इसका नुकसान उठाना पड़ता है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदर्श : बिरसा कृषि विवि के कुलपति जॉर्ज जॉन ने कहा कि देश की 70 फीसदी आबादी अब भी कृषि पर ही आश्रित है.

वर्तमान की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदर्श योजना है. ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं, सिविल सोसाइटी के माध्यम से योजना को गांव-गांव तक ले जाने की आवश्यकता है.

परंपरागत कृषि पद्धति से कठिनाई : कृषि निदेशक जटाशंकर चौधरी ने कहा कि झारखंड में औसतन 1300 मिली. तक बारिश होती है. सूखाड़ वाले समय में भी 900 मिली. तक बारिश होती है. इसके बावजूद हमारे यहां कृषक समाज चुनौतियों से जूझ रहा है.

परंपरागत कृषि पद्धति से बंधे होने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. 38 लाख योग्य कृषि भूमि हमारे राज्य में है, परंतु 26 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही खेती हो पा रही है. प्रधामंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी प्रकार की फसलों को शामिल किया गया है. स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकते हैं. मौके पर बिरसा कृषि विवि के वरीय अधिकारी आरपी सिंह रतन, पीएचडी चेंबर, झारखंड चैप्टर के चेयरमैन पवन बजाज, एसके सेठी, दुर्गेश शर्मा, जितेंद्र नारायण सिंह, फरहा तबस्सूम, नीता प्रसाद सहित विभिन्न बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे. संचालन इंश्योरेंस कमिटी के प्रमुख योगेश व धन्यवाद ज्ञापन देवजीत तालापात्र ने दिया.

Follow us on: @TheDailyPioneer facebook.com/dailypioneer

RNI Regn. No. JHAENG/2008/22930, R

OPINION 8
PAKISTAN'S DREAMS OF DISBALANCE, DISRUPTION

WORLD 12
CHINA RELEASES WHITE PAPER TO REFUTE SCS TRIBUNAL VERDICT

SPORT 15
INDIA PLAY FINAL WARM-UP GAME VS WICB TODAY

DELHI LUC
BHUBANESWAR
CHANDIGA
*Air S
JOSHILA
FIRST M
WATCHE
13 VIVA

RANCHI, THURSDAY JULY 14, 2016; PAGES 16 ₹3

the pioneer

Roy to farmers: Use crop insurance as your

PNS ■ RANCHI

Parliamentary Affairs, Food, Public Distribution and Consumer Affairs Minister Saryu Roy urged farmers to use Prime Minister Crop Insurance Scheme (PMCIS) as their right.

In a programme organised by Jharkhand Committee of PHD Chamber of Commerce and Industry and Government of Jharkhand, Roy said on Wednesday that crop insurance was not alms to farmers from the Government but it was their right, and they must come forward to avail it.

Describing PMCIS as one of the best plans for farmers by PM Narendra Modi, Roy said that it was not the first time that something like crop insurance policy was launched. "Serious thoughts about crop insurance have been on papers since early 70s of last century. There was a crop insurance plan launched around mid 80s and another around first years of this century as well. But this is the first time that a comprehensive and collective thought has been given to this plan. This is why farmers have been given unparalleled profits keeping their premium at lowest ever and maximising their compensation," Roy said.

Earlier in the day, Jharkhand Committee of PHD Chamber of Commerce and Industry Chairman Pawan Bajaj said while beginning the programme that the organisation was all set to take the initiative of spreading awareness about PMCIS in districts and villages provided that proper support from the government was assured. He added that in a state where farmers have still not been provided sufficient water for irrigation and they don't get even Minimum Support Price (MSP) of their crops at times, an almost error-free plan like this one would help a lot to farmers of the state.

"The (central) government has come up with an excellent programme and farmers must take benefit from it. You will find all hurdles of earlier similar programmes removed this time. Jharkhand is a state of farmers where agriculture largely remains rain-fed, hence always at risk," Bajaj said.

The programme was organised to spread awareness about PMCIS among farmers. Jharkhand has set a target to have 50 per cent farmers under PMCIS in three years.

Opposing heavily to those advocating 'industry' status to agriculture, Roy said that it was not at all in favour of agriculture. "If giving industry status to agriculture was any answer, no industry in the country would have ever suffered at first place. We have to work to make farming easy and farmers prosperous. Industrialization of agriculture sector would only destroy it," he said. He also persuaded farmers to adopt fortified grains and mixed crops to increase their source of income.

According to the Minister, most of the states have begun to cooperate with the centre in the execution of its agrarian policies including those of insurances but few states have yet to come forward on this front. He, however, added that persuasive efforts of the centre in this direction are on and the recalcitrant states would fall in line so that the growth of the agriculture sector also accelerates.

Director, Agriculture, Jata Shanker Choudhary said on the occasion that Jharkhand has 38 lakh acres of agri-field, in which 26 lakh acres were being used for agriculture.

Continued on Page 2

Parliamentary Affairs Minister Saryu Roy (second from right) addresses a seminar on 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna' at Birsa Agric Wednesday. Chairman Jharkhand Committee PHD Chamber Pawan Bajaj, Chairman Insurance Committee and CEO & MD IFFCO TOK Lohiya, Vice Chancellor BAU Dr. George John are also seen in the picture